



2026:AHC:67382

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत सं - 6443 वर्ष 2026

शिव कुमार सोलंकी आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: योगेश कुमार तिवारी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 74

माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक वर्मा

1. आवेदक के अधिवक्ता को सुना, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. यह आवेदन विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट-I, बांदा द्वारा शिकायत मामले संख्या-669/9/2025 (अयोध्या प्रसाद सिंह बनाम शिव कुमार सोलंकी) की धारा 138 एन.आई. अधिनियम, थाना-कोतवाली नगर, जिला-बांदा में पारित समन आदेश दिनांक 09.10.2025 को रद्द करने के लिए दायर किया गया है।
3. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 09.10.2025 के आदेश के तहत समन जारी किया गया था, इसके बाद तारीख 14.11.2025 निर्धारित की गई थी। 14.11.2025 को, विद्वान मजिस्ट्रेट ने जमानती वारंट जारी किया और अगली तारीख 08.12.2025 निर्धारित की। 08.12.2025 को, विद्वान मजिस्ट्रेट ने उपस्थित न होने पर आवेदक के खिलाफ गैर जमानती जंग जारी की। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट न्यायिक दिमाग का अनुप्रयोग नहीं है।



4. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि आवेदक के खिलाफ जारी वारंट न्यायिक दिमाग के अनुप्रयोग के बिना है, क्योंकि आदेश दिनांक 09.10.2025 के तहत नोटिस जारी किया गया था और 14.11.2025 के लिए तारीख तय की गई थी और 14.11.2025 को जमानती वारंट जारी किया गया है और 08.12.2025 को तारीख तय की गई थी और अगली तारीख यानी 08.12.2025 को आवेदक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया मनमाना और अवैध है और इसे इसके द्वारा रद्द/अपास्त किया जाता है, जबकि, आवेदक को कार्यवाही के लंबित होने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और समन जारी होने पर भी उसे जानकारी मिली थी। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया समन न्यायसंगत और उचित है।

5. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक मामले को निपटाने के लिए तैयार है।

6. आवेदक के अधिवक्ता ने दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच., 2010 (5) एस.सी.सी. 663 में रिपोर्ट किए गए मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। प्रासंगिक प्रस्तर-17, 18 और 19 यहां नीचे उद्धृत किए गए हैं: -

"17. हाल ही में प्रकाशित एक टिप्पणी में, अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं [से उद्धृत: अरुण मोहन, धारा 138 के विषय पर कानून सुधारों के प्रति कुछ विचार, परक्राम्य लिखत अधिनियम-मामलों के हिमस्खलन से निपटना (नई दिल्ली: यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, 2009) पृष्ठ 5 पर] :

"... अपराध के अन्य रूपों के विपरीत, यहां सजा (जहां तक शिकायतकर्ता का संबंध है) प्रतिशोध मांगने का साधन नहीं है, बल्कि पैसे का भुगतान सुनिश्चित करने का एक साधन है। शिकायतकर्ता का हित मुख्य रूप से चेक के दराज को जेल में देखने के बजाय पैसे की वसूली में निहित है। जेल की धमकी वसूली सुनिश्चित करने का एक तरीका है। जहां तक आरोपी जेल की सजा काटने को तैयार है, चेक धारक के लिए उपाय के रूप में बहुत कम उपलब्ध है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यदि हम एक तरफ अंतिम फैसले से पहले दायर की गई शिकायतों की संख्या-की जांच करें और दूसरी तरफ निर्णय और दोषसिद्धि के लिए आगे बढ़े वाले मामलों की संख्या-की जांच करें, तो हम पाएंगे कि बड़ी संख्या-का निपटारा किया गया था और केवल एक छोटी संख्या-जारी थी।

18. यह बिल्कुल स्पष्ट है कि चेक के अनादर के अपराध के संबंध में, यह उपाय का प्रतिपूरक पहलू है जिसे दंडात्मक पहलू पर दायर की जानी चाहिए। अटॉर्नी जनरल द्वारा उठाई गई आशंकाओं के लिए भी कुछ समर्थन है कि अधिकांश चेक बाउंस मामलों को वास्तव में समझौता किया जा रहा है या शमन के माध्यम से सुलझाया जा रहा है, हालांकि मुकदमेबाजी के बाद के चरणों के दौरान न्याय वितरण में अनुचित देरी में योगदान देता है। यहां समस्यावादियों की प्रवृत्ति के साथ है कि वे अपने विवाद को हल करने के साधन के रूप में देर से शमन का चयन करते हैं।

19. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अटॉर्नी जनरल का निवेदन यह है कि वैधानिक मार्गदर्शन के अभाव में, पक्षगण अंतिम उपाय के रूप में शमन का चयन कर रही हैं, जैसे ही मजिस्ट्रेट शिकायतों का संज्ञान लेते हैं। इस तरह के व्यवहार के लिए एक स्पष्टीकरण यह हो सकता है कि आरोपी व्यक्ति मुकदमेबाजी के विभिन्न चरणों के माध्यम से आगे बढ़ने का मौका लेने के लिए तैयार हैं और फिर निपटान का मार्ग तभी चुनते हैं जब कोई अन्य मार्ग नहीं रहता है। हालांकि इस तरह के व्यवहार कोवादियों के दृष्टिकोण से तर्कसंगत माना जा सकता है, कठिन तथ्य यह है कि शमन का विकल्प चुनने में अनुचित देरी विभिन्न स्तरों पर अदालतों के समक्ष लंबित बकाया में योगदान करती है। यदि अभियुक्त मुकदमेबाजी के बाद के चरण में अपराध के शमन के माध्यम से समझौता करने या समझौता करने के लिए तैयार है, तो यह आम तौर पर शिकायतकर्ता के मामले में कुछ योग्यता का संकेत है। ऐसे मामलों में यह वांछनीय होगा यदि पक्ष मुकदमेबाजी के पहले चरणों के दौरान शमन का चयन करते हैं। हालांकि, यदि आरोपी के पास



अन्य आधारों के बीच गलती, जालसाजी या जबरदस्ती जैसे वैध बचाव हैं, तो मामले पर निर्दिष्ट मंचों के माध्यम से मुकदमा चलाया जा सकता है।

7. जैसा कि अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया है, यह निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्त आज से एक महीने की अवधि के भीतर प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता के माध्यम से अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सकता है और समझौता के माध्यम से अपराध के शमन की मांग करने वाला एक आवेदन पेश कर सकता है और चेक राशि का 10% जमा कर सकता है। इस तरह के आवेदन पर संबंधित अदालत इस संबंध में कानून के अनुसार पर्याप्त कदम उठा सकती है और आरोपी को इस दिशा में प्रयास करने के लिए आज से अधिकतम चार महीने की अवधि से अधिक नहीं होने का अवसर प्रदान करेगी। इसके बाद, अदालत आज से पांच महीने की अवधि के भीतर दामोदर एस. प्रभु (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से आवश्यक आदेश पारित करेगी।

8. यदि आवेदक समझौते के माध्यम से अपराध के शमन के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उपस्थित होने और मुकदमे का सामना करने की आवश्यकता होती है और अदालत अभियुक्त के खिलाफ कानून के अनुसार आगे बढ़ने और कानून की अनुमति के अनुसार उसकी उपस्थिति प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम और उपाय करने के लिए स्वतंत्र होगी।

9. पांच महीने की उपरोक्त अवधि में या आवेदन के आलोक में दिए गए निर्णय तक, जो भी पहले हो, अभियुक्त के खिलाफ कोई बलपूर्वक उपाय नहीं अपनाया जाएगा।

10. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश केवल उन अभियुक्तों के संबंध में पारित किया गया है जिनकी ओर से धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत यह आवेदन इस न्यायालय में दायर किया गया है।

11. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ इस आवेदन का निस्तारण किया जाता है।

मार्च 31, 2026

नितिन वर्मा

(न्यायमूर्ति दीपक वर्मा)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।